कर्मचारियों को अधिकार दिये गये हैं और ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा क्या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए इन कर्मचारियों ने पर्याप्त उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उपायों की जांच की है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या कमियां पाई गई हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसी धोखाधड़ियों को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए अधिक कड़े कदम उठाने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (घ) बैंकों ने दिन-प्रतिदिन के परिचालनों के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं निधारित कर रखी है। धोखाधड़ियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का कार्याकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया जाता है और अनुपालन न करने वालों का पता लगाया जाता है तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रयोजन के लिए, बैंकों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है। इसमें शामिल है (i) नियंत्रक कार्यालय जो नियमित नियंत्रण, विवरणियों, शाखाओं के दौरे, आदि के माध्यम से अपने प्रभाराधीन शाखाओं की निगरानी करते हैं: (ii) आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्र जो शाखाओं की आवधिक जांच और लेखा परीक्षा करते है और शाखाओं और नियंत्रण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के विभागों के कार्यकरण में पाई गई अनियमितताओं/खामियों को बताते हैं। आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, बैंक उपचारात कार्रवाई करते हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास सतर्कतातंत्र हैं जो निराधात्मक और पता लगाने वाले कदम उठाने के लिए उत्तरदायी हैं ताकि बैंक कर्मचारियो द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी और भ्रष्ट कार्यों को रोका जा सके। सतर्कता तंत्र उपयुक्त विभागीय कार्रवाई करने के लिए सतर्कता की प्रकृति वाले मामलों को अनुशसिनिक प्राधिकारी के पास भेजता है। बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक आतंरिक निरीक्षण तंत्र और सतर्कता तंत्र के कार्यकरण की भी सतत् समीक्षा करते हैं। वे उन धोखाधड़ियों की भी समीक्षा करते हैं जिनका पता चला है ताकि उनके हेतु कारणों का पता लगाया जा सके और प्रणालियों और प्रक्रियाओं में विद्यमान कमियों/खामियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाते हैं। निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न होने और बिना समय गवाएं इसके कारण हुई धोखाधड़ियों का पता लगाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपनी बड़ी और अत्यधिक बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए कहा है। सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में धोखाधड़ियों और अनाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (घोष समिति) गठित की थी। इस समिति की अधिकांश सिफारिशें बैंक को तत्काल कार्यान्वयन के लिए 1992 में भेज दी गई थीं।

Development of tourist places in Rajasthan and Orissa

2976. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken any concrete measures to launch some new projects in Rajasthan and Orissa to develop tourism in these States; and

(b) if so, the details thereof during the last two years and upto 30.6.1996 including the number of hotels, motels and guest houses built in these States to meet the rush of foreign/ Indian tourists?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANTA JENA): (a) The Department of Tourism in consultation with the State Government of Rajasthan and Orissa have identified following projects for providing central financial assistance during 96-97.

Projects in Rajasthan

1. Extension of Tourist Bungalow at Gangaur.
2. Tourist Bungalow at Ajmer.
3. Tourist Bungalow at Mount Abu.
4. Tourist Bungalow at Churu.
5. Tourist Bungalow at Jhunjunu.
6. Cafeteria at Osian.

Projects in Orissa

1. Wayside amenities at Ghatgaon.
2. Tourist Complex at Denkanal.
3. Wayside amenities at Satpara.

(b) The detail of projects for which financial assistance has been extended by the Department of Tourism during the last.two years to the Government of Rajasthan & Orissa

are as given below:
Projects in Rajasthan

1. Tourist Bungalow ot Hanumangaih
2. Tourist Bungalow at Bhilwara.
3. Wayside amenities at Santhore
4. Wayside amenities at Bapp.
5. Assistance for Shilpgram Utsav.
6. Shilpgram Utsav 1992.
7. Yatrika at Ajmer.
8. Pilgrim shed atVishram Sthali.
9. Yatrika at mahandipur-ka-Babaji.
10. Yatrika at Kailadevi.
11. Camping site at Jhalawar.
12 Palace on Wheels.
13. Wayside amenities at Balesar.
14. Wayside facilities Fatehgarh.
15. Tourist cottages at Chotan.
16. Tourist amenities at Jhunjunu, Sekambar Mata & Lohargarh.
17. Midway at Merta.
18. Tourist Resort at Kiradu.
19. Tourist Complex at Khichan.
20. Tourist Resort at mahaveer Teeba.
21. Tourist amenities at Phalodi.
22. Conservation work at Osian Temples.
23. Conservation at Rani ka Mahal, Jaisalmer.
24. Development around Indira Gandhi Nagar.
25. Rajasthani Cultural Festival at Delhi Hatt.

Projects in Orissa

1. Tourist Complex at Hirakud.
2. Tourist lodge at Rayagada.
3. Tourist Complex at Narsinghnath.
4. Tourist Complex at Korapat.
5. Illumination of Sea Beach at Puri.
6. Beach Festibal 1994.
7. Rajaseri Festival 1995.
8. Amenities Centre at Dhauli.
9. Tourist lodge at Badarama.
10. Noating restaurant at Barkal.
11. Beach cleaners equipment Puri, Orissa.

Foreign Assistance/Loan/Grant received during 1995-96

2977. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 327 given in Rajya Sabha on 16th July, 1996 and state-

fa) the foreign assistance/loan/grant received during 1995-96; and

(b) the details of foreign investment made in the country and investment made by the country in the other countries during this period?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The details of foreign assistance/loans/grants received by india during 1995-96 are as under:

	(Rs. Crore) 1995-96 (Provisional)
Govt. Account	7646.07
Grants	1063.56
Non-Govt. Account	2302.19

(b) The direct foreign investment made in the country during the calendar year 1995 was Rs. 6370.16 crore.

Government of India has also approved overseas Indian investment totalling US $ 327.80 million during Financial Year 1995-96.

Assessing the progress of Rural Family Welfare Service in Maharashtra

2978. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the progress of rural family welfare services in Maharashtra;

(b) if so, the details thereof;

(c) how the rural populace in the State are being motivated for adopting family planning norms and what incentives are being given to men and women opting for sterilization in the State, with details;

(d) whether any targets have been fixed in this regard; and